[2024] 10 एस.सी.आर. 893 : 2024 आई.एन.एस.सी 772

सोमजीत मल्लिक

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या - 4190/2024)

14 अक्टूबर 2024

[जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा,* जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय द्वारा जांच के दौरान एकत्रित सामग्री पर विचार किए बिना एफआईआर, संज्ञान आदेश और उसके अनुसरण में कार्यवाही को रद्द करना उचित था।

हेडनोट्स †

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – दंड संहिता, 1860 – धारा 406, 420 – अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि पक्षों के बीच समझौते के अनुसार, ट्रक/ट्रेलर को अभियुक्त-प्रतिवादियों को 21 महीने के लिए मासिक किराए पर चलाने के लिए किराए पर दिया गया था, लेकिन पहले महीने का किराया देने के बाद, आश्वासन के बावजूद किराया नहीं दिया गया - आरोप पत्र दायर किया गया और सीजेएम द्वारा संज्ञान लिया गया, जबकि प्रतिवादियों द्वारा दायर धारा 482, सीआरपीसी के तहत आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था - उच्च न्यायालय ने जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर विचार किए बिना एफआईआर, संज्ञान आदेश और कार्यवाही को रद्द कर दिया:

निर्णय: यह तय करने के चरण में कि क्या आपराधिक कार्यवाही या एफआईआर को दहलीज पर ही रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, एफआईआर या पुलिस रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोपों, जिसमें जांच या पूछताछ के दौरान एकत्र की गई सामग्री भी शामिल है, को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या आरोपी के खिलाफ जांच या कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है - इस चरण में आरोपों की सत्यता का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए - अपराध करने के लिए आवश्यक घटक, मेन्स रीआ, एक तथ्य का प्रश्न है जिसका अनुमान प्रश्नगत कार्य के साथ-साथ आसपास की परिस्थितियों और आरोपी के आचरण से लगाया जाना चाहिए - इस प्रकार, जब अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने ट्रक को किराए पर लेने के बावजूद कई महीनों तक किराया नहीं दिया और इसके भुगतान के लिए झूठे वादे किए, तो प्रथम दृष्टया मामला, आरोपी की ओर से बेईमान इरादे को दर्शाता है, साथ ही यह भी कि क्या ट्रक का बेईमानी से निपटान किया गया था, जो आपराधिक विश्वासघात का मामला बनाता है। जांच की आवश्यकता है -

एफ.आई.आर को रद्द करने की याचिका धारा 173 (2), सी.आर.पी.सी के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर निष्फल नहीं हो जाती है, लेकिन जब आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, और यदि जांच पर कोई रोक नहीं है, तो अदालत को एफ.आई.आर और परिणामी कार्यवाही को रद्द करने से पहले पुलिस रिपोर्ट में सामग्री पर विचार करना चाहिए - खासकर जब एफ.आई.आर में आरोपी के बेईमान आचरण को दर्शाने वाला कृत्य आरोपित किया गया हो - एफ.आई.आर को शुरू में ही रद्द करना वैध जांच को विफल कर देगा - विवादित आदेश को अलग रखा गया - जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों पर विचार करने के लिए रद्द करने की याचिका उच्च न्यायालय को वापस भेज दी गई। [पैरा 16, 17, 19, 20, 22, 23]

आपराधिक कानून - एफ.आई.आर - रद्द करना - एफ.आई.आर रद्द नहीं की जाएगी, अगर संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है:

निर्णय: एफ.आई.आर सभी आरोपों का विश्वकोश नहीं है - यह जांचने के लिए कि क्या एफआईआर किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का खुलासा करती है, आरोपों में किसी चूक पर गौर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आरोपों के मूल तत्व पर गौर किया जाना चाहिए - इस स्तर पर, न्यायालय को यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा विशिष्ट अपराध किया गया है - केवल आरोप तय करने के समय, जब जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री न्यायालय के समक्ष होती है, तो उसे यह राय बनानी होती है कि किस अपराध के लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए - इससे पहले, यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त कर सकता है - इस प्रकार, जब एफ.आई.आर में अभियुक्त की ओर से बेईमानी का आरोप लगाया जाता है, जो सामग्री द्वारा समर्थित होने पर संज्ञेय अपराध के किए जाने का खुलासा करता है, तो एफ.आई.आर को रद्द करके जांच को विफल नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 17]

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860।

कीवर्ड की सूची

निरस्तीकरण; निरस्तीकरण याचिका; संज्ञान आदेश; जांच के दौरान एकत्रित सामग्री; किराए पर ट्रक; किराया शुल्क; ट्रक किराए पर लिया गया; बेईमान इरादा; तथ्य का मेन्स रीआ प्रश्न; संज्ञान; आरोप पत्र; पुलिस रिपोर्ट; एफआईआर विश्वकोश नहीं; आपराधिक विश्वासघात।

सोमजीत मल्लिक बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य

मामला उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या - 4190/2024

झारखंड उच्च न्यायालय रांची के आपराधिक विविध याचिका संख्या - 3796/2018 के दिनांक 01.02.2024 के निर्णय एवं आदेश ।

पार्टियों में उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए - कोणार्क त्यागी, सागर सारदा, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों के लिए - राहुल श्याम भंडारी, सुश्री जी प्रियदर्शिनी, सत्यम पाठक, प्रभाकर पाहेपुरी, डॉ. रत्नेश्वर चकमा, विष्णु शर्मा, सुश्री मधुस्मिता बोरा, शिव राम शर्मा, पवन किशोर सिंह, दीपांकर सिंह, श्रीमती अनुपमा शर्मा, अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट/आर्डर

<u>जजमेंट/निर्णय</u>

<u>मनोज मिश्रा, जे.</u>

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. यह अपील आपराधिक विविध याचिका संख्या 3796/2018 में पारित उच्च न्यायालय [1] के दिनांक 01.02.2024 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसके तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 [2] की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.02.2020 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा संज्ञान लिया गया था, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट [3], जमशेदपुर की अदालत में लंबित जी.आर. संख्या 1627/2016 के अनुरूप, थाना - साकची में पंजीकृत केस संख्या 78/2016 के संबंध में सभी आगे की कार्यवाही।

<u>तथ्यात्मक मैट्रिक्स</u>

3. अपीलकर्ता (मूल शिकायतकर्ता) ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि दूसरे और तीसरे प्रतिवादी (मूल आरोपी) ने अपीलकर्ता के ट्रक (ट्रेलर संख्या - एनएल 01 के 1250) को टाटा स्टील जमशेदपुर और कलिंगनगर के बीच चलाने के लिए चालक/सहायक के वेतन को

1 झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
2 सी.आर.पी.सी
3 सी.जे.एम

छोड़कर 33,000/- रुपये मासिक किराए पर लेने की पेशकश की; उस प्रस्ताव के अनुसार, अपीलकर्ता और आरोपी के बीच 10.07.2014 को एक समझौता हुआ, जिसके तहत वाहन को 14.07.2014 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए आरोपी को किराए पर दिया गया; और इसके बाद, ट्रक का कब्जा आरोपी को दे दिया गया। बदले में, उन्होंने टीडीएस काटने के बाद एक महीने का किराया दिया। लेकिन उसके बाद, हालांकि ट्रक जुलाई 2014 से आरोपी के कब्जे में था, लेकिन बार-बार झूठे आश्वासन के बावजूद बकाया राशि सहित 12,49,780 रुपये का भुगतान नहीं किया गया।

4. धारा 156(3) सी.आर.पी.सी के तहत उपरोक्त आवेदन पर, विद्वान सी.जे.एम ने दिनांक 12.11.2016 के आदेश के तहत पुलिस को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया।

5. जांच के दौरान जब धारा 41ए सी.आर.पी.सी के तहत नोटिस के बावजूद आरोपी पेश नहीं हुआ तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू[4] जारी करने के लिए सी.जे.एम को आवेदन दिया। उक्त आवेदन को 30.06.2017 के आदेश के तहत स्वीकार कर लिया गया।

6. दिनांक 30.06.2017 के आदेश से व्यथित होकर, दूसरे और तीसरे प्रतिवादियों ने धारा 482 सी.आर.पी.सी के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें उक्त आदेश को रद्द करने के साथ-साथ थाना - साकची में केस संख्या 78/2016 के रूप में दर्ज एफ.आई.आर[5] के अनुसार कार्यवाही करने की मांग की गई।

7. धारा 482 सी.आर.पी.सी के तहत आवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह आरोप लगाया गया था कि कोई समझौता निष्पादित नहीं किया गया था; अपीलकर्ता टाटा स्टील फैक्ट्री के अंदर खड़े अपने ट्रक को किराए पर देना चाहता था, लेकिन एक महीने का अग्रिम किराया भुगतान करने के बावजूद, ट्रक से संबंधित आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए, इसलिए कोई समझौता निष्पादित नहीं किया गया; और भले ही यह मान लिया जाए कि समझौता निष्पादित किया गया था, धारा 406 और 420 आई.पी.सी के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनता है।

8. जबकि धारा 482 सी.आर.पी.सी के तहत आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, पुलिस रिपोर्ट पर, सी.जे.एम द्वारा 20.02.2020 को संज्ञान लिया गया था और धारा 204 सी.आर.पी.सी के तहत प्रक्रिया जारी की गई थी। नतीजतन, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 (मूल आरोपी) ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी प्रार्थना में संशोधन की मांग की ताकि संज्ञान आदेश को रद्द करने की प्रार्थना को शामिल किया जा सके।

4 गैर - जमानती वारंट

5 प्रथम सूचना रिपोर्ट

9. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में संज्ञान के आदेश और संबंधित मामले में आगे की सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया, जबकि मूल शिकायतकर्ता को सिविल उपचार का सहारा लेने का विकल्प खुला छोड़ दिया।

उच्च न्यायालय का तर्क

10. उच्च न्यायालय ने इस प्रकार तर्क दिया:

क. एफ.आई.आर में किसी तरह के विश्वास सौंपने का आरोप नहीं है, इसलिए धारा 406 आई.पी.सी[6] के तहत दंडनीय आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं बनता है।

ख. बेशक, एक महीने का किराया चुकाया गया था, इसलिए शुरू से ही बेईमानी का इरादा नहीं था। आवेदन केवल किराए की वसूली के लिए है, जिसे उचित सिविल कार्यवाही का सहारा लेकर वसूला जा सकता है। इसलिए, धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनता है।

11. उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर मूल शिकायतकर्ता हमारे समक्ष है।

12. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

13. अपीलकर्ता की ओर से यह दलील दी गई:

क. एफ.आई.आर में खुलासा किया गया है कि एक महीने का किराया देने के बाद भी झूठे आश्वासन के बावजूद किराया नहीं दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में जांच का मामला बनता है।

ख. उच्च न्यायालय ने जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर विचार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप आरोप पत्र दाखिल किया गया। चूंकि आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने से पहले जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर विचार करना चाहिए था कि अपराध किया गया है या नहीं।

ग. उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि ट्रक का पता नहीं था। अन्यथा भी, चूंकि ट्रक वापस नहीं किया गया था, इसलिए यह माना जा सकता है कि इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है या आरोपी द्वारा समझौते का उल्लंघन करके निपटाया गया है, जिससे आपराधिक विश्वासघात का अपराध सामने आता है।

[6] भारतीय दंड संहिता, 1860

अभियुक्त-प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुतियाँ

14. आरोपी प्रतिवादियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया:

क. एफ.आई.आर में किसी अपराध का खुलासा नहीं किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पूरी कार्यवाही को रद्द करना उचित था।

ख. एफ.आई.आर में ट्रक के निपटान या दुरुपयोग के संबंध में कोई विशेष आरोप नहीं था, इसलिए आपराधिक विश्वासघात का कोई मामला नहीं बना।

ग. धोखाधड़ी का अपराध नहीं बनता क्योंकि एफ.आई.आर में शुरू से ही बेईमानी का आरोप नहीं लगाया गया है।

घ. उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान आदेश को रद्द करने और आगे की कार्यवाही को उचित ठहराया गया।

राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

15. राज्य की ओर से हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया गया कि मूल शिकायतकर्ता ने सूचित किया था कि पक्षों के बीच समझौते के अनुसार ट्रक/ट्रेलर को आरोपी को चलाने के लिए किराए पर दिया गया था। हालांकि, ट्रक का वर्तमान स्थान न तो मूल शिकायतकर्ता को पता था और न ही काफी प्रयासों के बावजूद पता लगाया जा सका।

विश्लेषण

16. इससे पहले कि हम आरोपित आदेश की सत्यता का परीक्षण करें, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह तय करने के चरण में कि आपराधिक कार्यवाही या एफ.आई.आर, जैसा भी मामला हो, को सीमा पर रद्द किया जाना है या नहीं, एफ.आई.आर या पुलिस रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोपों, जिसमें जांच या पूछताछ के दौरान एकत्र की गई सामग्री भी शामिल है, को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आरोपी के खिलाफ जांच या कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। इस चरण में आरोपों की सत्यता का परीक्षण नहीं किया जाना है।

17. किसी अपराध को करने के लिए, जब तक कि दंड विधान में अन्यथा प्रावधान न हो, मेन्स रीया एक आवश्यक तत्व है। मेन्स रीया का अस्तित्व एक तथ्य का प्रश्न है जिसका अनुमान प्रश्नगत कार्य के साथ-साथ आस-पास की परिस्थितियों और आरोपी के आचरण से लगाया जा सकता है। अनुक्रम के रूप में, जब कोई पक्ष यह आरोप लगाता है कि आरोपी ने ट्रक को किराए पर लेने के बावजूद, कई

महीनों तक किराया नहीं दिया है, जबकि इसके भुगतान के लिए झूठे वादे किए हैं, तो प्रथम दृष्टया मामला आरोपी की ओर से बेईमान इरादे को दर्शाता है, जिसकी जांच की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, यदि एफआईआर को शुरू में ही रद्द कर दिया जाता है, तो यह एक वैध जांच को विफल करने वाले कृत्य से कम नहीं होगा।

18. यह एक सामान्य कानून है कि एफ.आई.आर सभी आरोपों का विश्वकोश नहीं है। इसलिए, यह जांचने के लिए कि क्या एफ.आई.आर किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, आरोपों में किसी चूक को नहीं बल्कि उसमें निहित आरोपों के सार को देखा जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध किया गया है या नहीं। इस स्तर पर, न्यायालय को यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा विशिष्ट अपराध किया गया है। जांच के बाद ही, आरोप तय करने के समय, जब जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री न्यायालय के समक्ष होती है, न्यायालय को यह राय बनानी होती है कि किस अपराध के लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इससे पहले, यदि संतुष्ट हो, तो न्यायालय अभियुक्त को दोषमुक्त भी कर सकता है। इस प्रकार, जब एफ.आई.आर में अभियुक्त की ओर से बेईमानी का आरोप लगाया जाता है, जो सामग्री द्वारा समर्थित होने पर संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है, तो एफ.आई.आर को रद्द करके जांच को विफल नहीं किया जाना चाहिए।

19. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सी.आर.पी.सी की धारा 173 (2) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर एफ.आई.आर को रद्द करने की याचिका निरर्थक नहीं हो जाती है, लेकिन जब पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, खासकर जब जांच पर कोई रोक नहीं है, तो अदालत को यह निर्णय लेने से पहले पुलिस रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना चाहिए कि एफ.आई.आर और परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं। खासकर तब, जब एफ.आई.आर में किसी ऐसे कृत्य का आरोप लगाया गया हो जो अभियुक्त के बेईमान आचरण को दर्शाता हो।

20. इस मामले में, एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने मूल शिकायतकर्ता के ट्रक/ट्रेलर को 14.07.2014 से 31.03.2016 तक 33,000/- रुपये मासिक किराए पर किराए पर लिया था, लेकिन पहले महीने का किराया देने के बाद, झूठे आश्वासन के बावजूद किराया नहीं दिया गया। यह आरोप कि किराया खुद नहीं दिया गया, सामान्य तौर पर वाहन पर आरोपी का कब्जा होना माना जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में उस ट्रक का क्या हुआ, यह जांच का विषय बनता

है। यदि आरोपी ने इसे बेईमानी से बेचा होता, तो यह आपराधिक विश्वासघात का मामला बन सकता है। इसलिए, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को देखे बिना एफ.आई.आर को तुरंत रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था।

21. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय को एफ.आई.आर, संज्ञान आदेश और उसके अनुसरण में कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना पर निर्णय लेने से पहले जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों पर विचार करना चाहिए था।

22. पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन करने और यह समझने के लिए कि पुलिस ने किस प्रकार की जांच की है, 19.07.2024 को हमने राज्य से आरोप-पत्र रिकॉर्ड पर रखने की मांग की। हालांकि, दुर्भाग्य से, हालांकि राज्य ने अपना हलफनामा दायर किया, आरोप-पत्र पेश नहीं किया गया। राज्य द्वारा दायर हलफनामे से केवल यह संकेत मिलता है कि वे ट्रक/ट्रेलर का पता लगाने में सक्षम नहीं थे। इन परिस्थितियों में, हमारे पास जांच के दौरान जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्रियों पर विचार करने के बाद कानून के अनुसार नए सिरे से रद्द करने की याचिका पर फैसला करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

23. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। निरस्तीकरण याचिका को उसके मूल क्रमांक पर बहाल किया जाएगा और उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार तथा उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। सभी तर्क और दलीलें पक्षकारों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए खुली रखी गई हैं।

24. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटारा कर दिया गया है।

परिणाम : **अपील स्वीकार की गई।**

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।